

दैनिक

राज्य पत्रिका

वर्ष : 13

अंक : 129

पेज : 8

जयपुर, गुरुवार 17 अप्रैल 2025

मूल्य: 1.50 रुपये

यह प्रयोग महाराष्ट्र की मनमाड-सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12110) में किया गया एटीएम ऑन व्हील्स... भारत में 'पहली बार' ट्रायल के तौर पर ट्रेन में लगाई गई एटीएम

एजेसी | नई दिल्ली

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) लगाकर सफल परीक्षण किया है। जो अपने आप में सबसे बड़ी पहल है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका वीडियो भी साझा किया है। जिसमें एटीएम को ट्रेन में कहां लगाया गया है, इसे समझाया गया है। इस खास पहल का मकसद जनता को ट्रेन के सफर के दौरान भी पैसे निकालने की सुविधा देना है। इस तरह का पहला प्रयोग महाराष्ट्र की मनमाड-सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12110)

में किया गया है। इस पहल को - एटीएम ऑन व्हील्स - नाम दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस एटीएम की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर की है, जो खूब चर्चा में है। यह पहल रेलवे बोर्ड के उस निर्देश का हिस्सा है जिसमें कहा गया था कि यानि किराए के अलावा कमाई बढ़ाने के लिए नई और नई सोच के तरीके अपनाए जाएं। इसी के तहत 25 मार्च 2025 को रेलवे ने सभी संभावित वेंडरों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में चलती ट्रेनों में मोबाइल एटीएम लगाने का विचार रखा गया, जिसे बाद में मंजूरी भी मिल गई।



25 मार्च 2025 को रेलवे ने सभी संभावित वेंडरों के साथ एक बैठक की। इसमें चलती ट्रेनों में मोबाइल एटीएम लगाने का विचार रखा गया, जिसे बाद में मंजूरी भी मिल गई

रबर पैड और बोल्ट्स की मदद से एटीएम को ट्रेन में झटकों और कंपन से बचाया गया



कैसे हुआ ट्रायल?

ट्रेन में एटीएम का का पहला ट्रायल 10 अप्रैल 2025 को मनमाड-सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया। ट्रेन के गिनी पेट्री (ओटे किवन) वाले हिस्से को एटीएम लगाने के लिए तैयार किया गया। रेलवे का मैकेनिकल टीम ने यह काम किया और एटीएम को सुरक्षित रूप से फिट किया। रबर पैड और बोल्ट्स की मदद से एटीएम को ट्रेन के चलने के दौरान लगने वाले झटकों और कंपन से बचाया गया। दो अभियंताओं ने उस जगह पर लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा बनी रहे।

इस पहल का उद्देश्य क्या है?

ट्रेन में एटीएम लगाने से यात्रियों को कहीं भी आते-जाते पैसे निकालने की सुविधा देना है। इसके अलावा किराए के अलावा रेलवे को अतिरिक्त कमाई का जरिया मिलना और साथ ही रेलवे को और आधुनिक और स्मार्ट बनाना है।

राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी सौगात

जयपुर, (राज्य पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवानों का साहस, सेवा भावना और बलिदान अतुलनीय है। पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक वचन और जीवन का एक अर्थ है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी सही मायनों में समाज के असली नायक हैं। वे हर दिन, हर मौसम, हर चुनौती के बावजूद निरंतर सेवा में जुटे रहते हैं। हर संकट में सबसे पहले खड़े होकर जान-माल की सुरक्षा करते हैं। शर्मा बुधवार को आरपीए में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड निरीक्षण के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रदेश के बहादुर पुलिसकर्मीयों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। पुलिसकर्मी अपने जीवन को समाज की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए समर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

हर मोर्चे पर मुस्तेदी से डटी रहती है पुलिस- मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की दाल बनकर हमारी हिफाजत करते हैं। ये कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही समाज के हर वर्ग की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि अपराध रोकथाम, आपदा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण तथा सामाजिक समरसता बनाए रखने सहित पुलिस हर मोर्चे पर मुस्तेदी से डटी रहती है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना भी है।

पुलिस और नागरिकों के बीच होना चाहिए नियमित संवाद- शर्मा ने कहा कि पुलिस और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद से आमजन में विश्वास के साथ अपराध पर प्रभावी नियंत्रण होता है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गांवों-मोहल्लों



में बैठके आयोजित की जानी चाहिए, जिससे लोगों को पुलिस के कार्यों को समझने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस को स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में जाकर कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। इससे युवाओं में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। पुलिस को शिकायतों के त्वरित निस्तारण और तकनीक के उपयोग से आपसी विश्वास को मजबूत करना चाहिए।

200 करोड़ रुपये से होगा पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गठन- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिसकर्मियों के हित में कदम उठा रही है। उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया जा सके। इसी दिशा में पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपये का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा। साथ ही, प्रदेश में कानून-व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 10 हजार पदों पर भर्ती को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, 5,500 नवीन पदों का सृजन किया गया है तथा इस वर्ष 3,500 नवीन पद सृजन प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक, कालीबाई व अमृतादेवी

महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना हेतु पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम के गठन हेतु प्रथम चरण में एक हजार कांस्टेबल के नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। साथ ही, पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग में कार्यरत लांगरियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि एवं 250 लांगरी पदों का सृजन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के पुलिस विभाग को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए इसी तरह नवाचार करती रहेगी।

350 करोड़ रुपये से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की होगी स्थापना- शर्मा ने कहा कि पुलिस मोबिलिटी के लिए लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं तथा आधुनिक उपकरणों के लिए 27 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र का क्रमोन्नयन एवं विस्तार कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित किए जाने के लिए नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इसी तरह 350 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत सरदार

पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना की जाएगी। इसी तरह पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यक्षम बनाने हेतु करीब 60 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने परेड ग्राउण्ड में परेड निरीक्षण किया। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारी एवं कार्मिकों को पुलिस पदक तथा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के वर्दी भत्ते को 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने तथा पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मस भत्ता 2,400 रुपये से बढ़ाकर 2,700 रुपये करने की घोषणा की। शर्मा ने कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को समय पर पदोन्नति देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। हमारी सरकार पुलिसकर्मियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी।

नेशनल हेराल्ड केस में ED की चार्जशीट से सियासी हलचल -जयपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, गहलोत-पायलट ने साधा केंद्र पर निशाना

जयपुर। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ED की चार्जशीट दाखिल होने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। ईडी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट की शुरुआत दोपहर करीब 12 बजे हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता, विधायक और पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में प्रदर्शन स्थल पर लोग जुटे, जिन्होंने केंद्र सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, 'देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। भाजपा बार-बार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। ये बहुत खतरनाक है। ED पहले भी इस मामले की जांच कर चुकी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट भी मिल चुकी है। लेकिन, अब फिर से मामला शुरू कर दिया। ये झूठा मामला है, इसमें कोई दम नहीं है।' राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, 'भाजपा सत्ता में आने के बाद से ही राष्ट्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। चाहे वह ED हो, इनकम टैक्स हो या CBI। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है,



एक भी पैसे का लेन-देन नहीं हुआ है। यह एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है। जिस परिवार ने अपनी संपत्ति दान कर दी, आज आप उन्हें कैसे परेशान कर रहे हैं? क्या ईडी ने आज तक किसी भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की है।' वहीं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, 'पूरा देश जानता है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार के राजनीतिक हथियार हैं। सोनिया गांधी का जीवन सार्वजनिक है, यह उनकी

छवि खराब करने का प्रयास है। तथ्यों पर गौर करें तो इस मामले में कोई दम नहीं है। यह स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित मामला है जिसे लंबे समय से खींचा जा रहा है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम इसे कानूनी तरीके से सुलझा लेंगे।' राजस्थान सरकार ने क्या कहा? नेशनल हेराल्ड केस में ED की कार्रवाई पर राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, 'कांग्रेस का घोटालों का इतिहास रहा है। कोयला घोटाले से लेकर

देश में हुए अधिकांश घोटाले कांग्रेस के नाम पर हैं। जांच एजेंसी लंबे समय से नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कर रही है। लंबी जांच के बाद, कई तथ्यों और दस्तावेजों पर रिकॉर्ड लेने के बाद अगर ED कोर्ट में चालान पेश करती है और कांग्रेस उसका विरोध करती है, तो कांग्रेस घोटाले बचाने में लगी है। उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा न रखने वाले ही ऐसी बयानबाजी करते हैं।

उर्दू हमारी जमीन से जन्मी... इसे धर्मों में न बांटो: उर्दू पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उर्दू में साइन बोर्ड को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि भाषा एक संस्कृति है और यह लोगों को आपस में बांटने की वजह नहीं बननी चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उर्दू हमारी गंगा-जमुनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब का शानदार नमूना है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने यह टिप्पणी की।

क्या है मामला? अदालत में महाराष्ट्र के अकोला जिले में पंचायत नगर पालिका परिषद की इमारत के साइनबोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती दी गई थी। अदालत ने इसे लेकर पूर्व पार्षद ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'किसी भाषा के प्रति हमारी गलत धारणाओं और पूर्वाग्रहों को सच्चाई से परखा जाना चाहिए। आइए, हम उर्दू और हर भाषा से दोस्ती करें।' कोर्ट ने आगे कहा, 'यह गलत धारणा है कि उर्दू भारत के लिए विदेशी है, उर्दू ऐसी भाषा है जो हमारी ही धरती पर पैदा हुई है।' अदालत ने अपने फैसले में कहा, 'भाषा धर्म नहीं है और यह धर्म का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती, भाषा एक समुदाय, एक क्षेत्र, एक लोगों की होती है, न कि किसी धर्म की।' अदालत ने कहा कि हमें अपनी



विविधताओं का आदर करना चाहिए। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि Maharashtra Local Authorities (Official Languages) Act, 2022 या किसी कानूनी प्रावधान के तहत उर्दू के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'उर्दू के खिलाफ पूर्वाग्रह इस गलत धारणा की वजह से पैदा हुआ है कि उर्दू भारत के लिए विदेशी है। यह राय गलत है क्योंकि मराठी और हिंदी की तरह उर्दू भी एक इंडो-आर्यन भाषा है। उर्दू ऐसी भाषा है

जो हमारे देश में जन्मी है।' कोर्ट ने कहा कि उर्दू भारत में अलग-अलग संस्कृति से जुड़े लोगों की जरूरत के कारण विकसित हुई और ऐसे लोग आपस में बातचीत करना चाहते थे। फारसी के शब्द 'हिंदवी' से आया हिंदी शब्द अदालत ने फैसले में कहा, 'आज भी देश के आम लोगों की भाषा में उर्दू का इस्तेमाल होता है, भले ही उर्दू इसके बारे में बहुत ज्यादा पता न हो। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी में हर दिन की बातचीत उर्दू के शब्दों या उर्दू भाषा से निकले शब्दों के बिना नहीं हो सकती। हिंदी शब्द खुद फारसी के शब्द 'हिंदवी' से आया है।' अदालत ने यह भी कहा कि

संविधान के अनुच्छेद 348 के मुताबिक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है फिर भी कोर्ट में कई उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे वकालतनामा, दस्ती आदि। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के विचार को बरकरार रखते हुए कहा कि नगर पालिका परिषद का काम लोगों की सेवा करना और उनकी जरूरत को पूरा करना है। ऐसे में अगर नगर पालिका परिषद के इलाकों में रहने वाले लोग उर्दू जानते हैं तो कम से कम नगर पालिका के साइन बोर्ड पर आधिकारिक भाषा मराठी के अलावा उर्दू का इस्तेमाल करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

जस्टिस बी.आर. गवई होंगे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश, 14 मई को लेंगे शपथ

नई दिल्ली। न्यायमूर्ति बीआर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। 14 मई को शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार को जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के नाम की सिफारिश अगले सीजेआई के रूप में की है। सीजेआई खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। परंपरा के अनुसार, मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना के बाद

सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस गवई 13 मई को सीजेआई खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद 14 मई को 52वें सीजेआई बनेंगे। 24 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए जस्टिस गवई का सीजेआई के रूप में कार्यकाल छह महीने से अधिक होगा। वह 23 नवंबर, 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कानून मंत्रालय ने पहले औपचारिक रूप से न्यायमूर्ति खन्ना से उनके उत्तराधिकारी का नाम बताने का अनुरोध किया था, और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। बीआर गवई का जन्म 24 नवंबर



1960 को अमरावती में हुआ है। वे 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए। न्यायमूर्ति गवई ने 14 नवंबर, 2003 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अपना न्यायिक करियर

शुरू किया। 12 नवंबर, 2005 को स्थायी न्यायाधीश बने। उन्होंने मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में पीठों की अध्यक्षता करते हुए 15 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की।

जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल

-2 दिवसीय कार्यक्रम में 280 बीएलए शामिल

जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश के राजनीतिक दलों की जमीनी स्तर पर भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इन दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को प्रशिक्षण देने की पहल की है। आयोग के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीएम), नई दिल्ली में बुधवार से बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लगभग 280 बीएलए के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस नवाचार का शुभारम्भ हुआ।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस आयोजन की परिकल्पना आयोग द्वारा 4 मार्च, 2025 को राष्ट्रीय के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान किया गया था। आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित करते हुए जोर दिया है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951; निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960; चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर आयोग द्वारा



जारी मैन्युअल, दिशा-निर्देशों और निर्देशों में उल्लिखित उनकी भूमिका को समझने और उसे निभाने में मदद करेगा। प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नामांकन अथवा नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही, इन राजनीतिक हितधारकों को चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं और प्रक्रियाओं यथा मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतन और संशोधन तथा इनसे जुड़े फॉर्म और प्रारूप आदि से भी परिचित कराया गया। उल्लेखनीय है कि बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों

द्वारा नामित किया जाता है और वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार वृत्तरहित मतदाता सूचियां तैयार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हैं। प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूचियों के विषय में आपत्ति होने की स्थिति में अधिनियम की धाराओं 24(क) और 24(ख) के तहत पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों के उपयोग में भी जानकारी दी गई। राजस्थान में राजनीतिक दलों के 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने बैठकों में हिस्सा लिया। राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने भी

28 मार्च को राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इसमें राजनीतिक दलों की ओर से बूथ लेवल अभिकर्ताओं (बीएलए) को नामित करने, चुनावी प्रक्रिया में उनकी भूमिका और प्रशिक्षण आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस क्रम में आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों और प्रशिक्षण रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर पर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिनमें 1,100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की विशेष समीक्षा बैठक ली



जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत नवाचार अपनाते हुए नवीन उपकरणों के आविष्कार में भारत को अग्रणी बनाने, अधिक से अधिक पेटेंट स्वीकृत करवाने, पाठ्यक्रम में बौद्धिक क्षमता विकास के लिए विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप भारत वैश्विक स्तर पर ज्ञान संपन्न बने, इसके लिए सभी कार्य करें। उन्होंने राजस्थान के विश्वविद्यालयों को देशभर में अग्रणी किए जाने का भी आह्वान किया। राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी ने राजस्थान में विश्वविद्यालयों में नवाचारों के साथ वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा और शोध पर विशेष ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता जताई। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव भानु प्रकाश अटरू ने राजस्थान में कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित प्रगति के बारे में अवगत कराया।

संस्कारों से नई पीढ़ी को जोड़ने और नई शिक्षा नीति के आलोक में विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट पाठ्यक्रम तैयार कर अध्ययन अध्यापन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने 'नैक' के मापदंड के अनुसार विश्वविद्यालयों को अधिस्वीकृत करवाने के लिए कार्यवाही समयबद्ध करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप भारत वैश्विक स्तर पर ज्ञान संपन्न बने, इसके लिए सभी कार्य करें। उन्होंने राजस्थान के विश्वविद्यालयों को देशभर में अग्रणी किए जाने का भी आह्वान किया। राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी ने राजस्थान में विश्वविद्यालयों में नवाचारों के साथ वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा और शोध पर विशेष ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता जताई। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव भानु प्रकाश अटरू ने राजस्थान में कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित प्रगति के बारे में अवगत कराया।

व्यावहारिक तौर पर राजस्व आधारित मॉडल हो विकसित - दिया कुमारी



जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के समक्ष जवाहर कला केन्द्र के लिए की गई बजट घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बुधवार को पर्यटन भवन में शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा जेकेके महानिदेशक रवि जैन की वीसी द्वारा उपस्थिति में जेकेके की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती अलका मीणा द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जेकेके हेतु आवंटित बजट राशि 8 करोड़ का रचनात्मक विकास कार्य करवाये जाने के निर्देश देने के साथ ही जेकेके संचालन के लिए कला और कलाकार का संरक्षण करने हेतु व्यावहारिक तौर पर राजस्व आधारित मॉडल विकसित किए जाने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कला और क्राफ्ट संरक्षित और विकसित करने हेतु संकल्पित है। कला और कलाकारों को नियमित मंच उपलब्ध हो तो कलाएं और क्राफ्ट जीवित और संरक्षित रहेंगे। उन्होंने जेकेके में विभिन्न प्रदर्शन

स्थानों पर आने वालों को उस स्थान की विस्तृत जानकारी देने के लिए क्यूआर कोड लगाये जाने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने जेकेके के डेटा को डिजिटाइज्ड किये जाने, दैनिक होने वाले आयोजनों की आमजन को जानकारी देने के लिए हर बार लगाये जाने वाले होर्डिंग्स के स्थान पर होर्डिंग एलडीडी लगाए जाने, लाइब्रेरी का विकास करने, शिल्प ग्राम में राज्य भर के बेस्ट कला उत्पादों के बिस्की प्रदर्शन किये जाने के लिए आर्टिजन्स को नियमित अवसर दिए जाने के निर्देश दिए।

सौर ऊर्जा अपनाओ - बिजली का खर्चा बचाओ—

उपमुख्यमंत्री ने जेकेके में सोलर ऊर्जा का उपयोग करने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसा करने से बिजली का खर्चा बचेगा। जेकेके की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती अलका मीणा द्वारा आईटी और टेक्निकल कार्य के साथ सिविल कार्य करवाये जाने हेतु विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया।

नई शिक्षा नीति के आलोक में आपदा प्रबंधन एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा है कि शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को चुनौतियों से लड़ने वाला मन बनाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं में शिक्षा में जो बजट आवंटित किया है वह विद्यार्थियों के विकास के लिए है।

शिक्षा से विद्यार्थी का मन विकसित होता है तो अपने आप ही आपदाओं से जूझने के लिए समाज तैयार होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत मन, आचार, विचार भी विकसित होंगे। राज्यपाल ने विनोबा भावे के कथन की चर्चा करते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ और देश का झंडा बदला गया तभी शिक्षा नीति भी बनानी चाहिए थी। मगर यह बदली नहीं, इसलिए विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ी। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है वह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास से और विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने से जुड़ी है।

राज्यपाल बागडे बुधवार को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा अभियान) के अंतर्गत आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, सेवा भारतीय और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में आपदा प्रबंधन एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने "मानव जोड़ी आदमी जोड़ी" की शिक्षा दी है। इस शिक्षा का अर्थ है, मन से लोगों से संबंध बनाए। देश



प्रेम से युवा पीढ़ी जुड़े। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता बढ़े। इसलिए आदमी जोड़ने का कार्य हो। आदमी जोड़ने का अर्थ है, भारत को एक सूत्र में बांधा जाए। उन्होंने नकल मुक्त शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी तभी यह संभव हो सकेगा। उन्होंने रटाने की बजाय मन से पढ़ने, पढ़ाने लिए कार्य किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वही ज्ञान सार्थक है जो समय के साथ प्रासंगिक रहे। नई शिक्षा नीति इसी आधार पर तैयार की गई है। यह भारतीय ज्ञान परंपरा का वह आलोक है, जिसमें जीवन की तमाम आपदाओं से मुकाबला करने की दृष्टि है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आपदा के

बाद पुनर्वास के तरीके भी बताए गए हैं। आरंभ में उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने वाली संस्थाओं, कार्यक्रम अधिकारियों व स्वयंसेवकों को सम्मानित भी किया।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय ग्रंथों में बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के तरीके बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा में भूस्खलन से बचाव के लिए उचित स्थान पर घर बनाना, बाढ़ से बचाव के लिए बांध और नहरें बनाना, और सूखा से बचाव के लिए पानी का संरक्षण की परंपराएं हमारे यहां आपदा

प्रबंधन रूप में ही बनीं। उन्होंने राजस्थान में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख राजकुमार मटाले ने मुख्य वक्ता के रूप में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत देश में समय-समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए गए कार्यों के आलोक में पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में आपदा से बचाव के लिए मन से विद्यार्थी तैयार किए जाने पर जोर दिया। आरंभ में कॉलेज शिक्षा सचिव भानु प्रकाश अटरू, आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश बैरवा ने राजस्थान में कॉलेज शिक्षा की प्रगति और नई शिक्षा नीति, ज्ञान परम्परा और आपदा प्रबंधन के पाठ्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी।

जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक

जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी (रामजल सेतु लिंक) परियोजना प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जिसके माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई के साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य किया जाए। राज्य सरकार इसके लिए संबंधित विभाग को मानव संसाधन, नियमों में सरलीकरण सहित अन्य सभी सहायताएं उपलब्ध कराएंगी। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट

प्रस्तुत की जाए एवं भूमि अवाप्ति के कार्यों में समन्वय के लिए विशेष रूप से अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।

20 अप्रैल को होगी बैठक—

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हेड से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली हेतु संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। इसी क्रम में डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रैल को यमुनानगर में हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक 20 अप्रैल को पिलानी में होगी। उन्होंने अधिकारियों को नब्बे एवं अलाइमेंट की डिजाइन की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के पैकेज 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत विवरण एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना को त्वरित गति प्रदान करने के लिए प्रथम



चरण में 9,600 करोड़ रुपये के कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इस पैकेज में भूमि अवाप्ति के अलावा, वन क्लीयरेंस एवं अन्य क्लीयरेंस के कार्य में गति लाई जाए। उन्होंने इस परियोजना में अब तक हो चुकी अधिगृहीत भूमि पर कार्य प्रारंभ करने का सुझाव दिया। साथ ही, उन्होंने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए।

प्राकृतिक डिप्रेशन को जलाशयों में परिवर्तित के कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए—

शर्मा ने इंदिरा गांधी नहर विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी

पर बने हुए चार प्राकृतिक डिप्रेशन को जलाशयों में परिवर्तित के कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए जिससे कि चूरू, जैसलमेर और बीकानेर जिले में पेयजल उपलब्धता में अभिवृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की समीक्षा करते हुए कहा कि फव्वारा सिंचाई पद्धति को विशेष रूप से विकसित किया जाए। उल्लेखनीय है कि महाराजा गंगासिंह ने वर्ष 1927 में गंगनहर की शुरूआत की थी। हाल ही में मुख्यमंत्री के शिवपुर हेड निरीक्षण के दौरान वर्ष 2027 में शताब्दी वर्ष के रूप में माना जाने का फैसला लिया गया है।

बजट घोषणाओं एवं रात्रि विश्राम की समीक्षा बैठक



जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की विभागीय बजट घोषणाओं के कार्यों का शीघ्र समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्य में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को समय से घोषणाओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। दिलावर बुधवार को पंचायती राज भवन स्थित सभागार में विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की बजट घोषणाओं के लम्बित प्रकरणों, कार्यों के क्रियान्वयन एवं अधिकारियों के रात्रि विश्राम के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ करें। उन्होंने स्वामित्व योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई बजट घोषणाओं के लंबित प्रकरणों के त्वरित क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों और रात्रि विश्राम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में गंदगी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिस्वोरिटी (एफईएस) के साथ वनस्पति सीड बैंक के संबंध में एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। अंत में बैठक में डॉ. जोगाराम शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुहम्मद जुनेद, निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, श्रीमती सलोनी खेमका, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व अन्य विभागीय अधिकारी गण उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष देवनाली ने पूर्व राजपरिवार के अरविन्दसिंह मेवाड़ के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की



जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाली बुधवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय आयोजनों में भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष देवनाली बुधवार सुबह मिना से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से सिकंदर हाउस पहुंचे। देवनाली ने सिटी पैलेस स्थित शंभु निवास पहुंच कर उदयपुर के पूर्व राजपरिवार के अरविन्दसिंह मेवाड़ के निधन पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। देवनाली ने दिवंगत अरविन्दसिंह मेवाड़ के पुत्र डॉ. लक्ष्मणराजसिंह मेवाड़ सहित परिवारजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त कीं। इसके पश्चात विधानसभा अध्यक्ष गीतांजलि अस्पताल पहुंचे तथा वहां उपचाररत राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा के पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा की कुशलक्षेम जानी। इसके अलावा देवनाली ने उदयपुर में ही श्री नारायणलाल शर्मा के निवास पर पहुंचकर उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की।

हजरत बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती का 5 दिवसीय वार्षिक मेला 17 से

मनोहरपुर, (रॉयल पत्रिका)। ताला ग्राम पंचायत की ऊंची ढ़ेंगी पर विराजमान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिक हजरत बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला आलेह का पांच दिवसीय वार्षिक मेला 17 अप्रैल गुरुवार को कूल की रस्म के साथ में विधिवत शुरू होगा जो की 20 अप्रैल रविवार को कूल की रस्म के साथ में विधिवत शहरी मेला संपन्न होगा इसके बाद में 21 अप्रैल सोमवार को गुदड़ी मेला भरेगा। ग्राम पंचायत ताला के सरपंच अमीर खान शेख ने बताया कि 17 अप्रैल गुरुवार से शुरू होने वाले पांच दिवसीय सालाना मेले का आगाज दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म के साथ होगा 5 दिवसीय उर्स को लेकर दरगाह कमेटी सदस्य तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। दरगाह के खादिमान ने बताया कि 17 अप्रैल को पहाडगांज

जयपुर व भीलवाड़ा से आने वाले जायसीनों का जसा बाण गंगा नदी पुलिया पर शाम 5 बजे असर की नमाज़ अदा कर जुलूस के रूप में दरगाह पहुंचेंगे इसके बाद वहां बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म के साथ मेले का आगाज होगा। उर्स की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सतर्क है। ताला दरगाह के खादिमान ने बताया कि मेले की व्यवस्था को लेकर दरगाह कमेटी तैयारियों में जुटी हुई है।

दरगाह के खादिमानो ने बताया कि 18 अप्रैल शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी रात्रि 9 बजे बाद शाम को मिलाद शरीफ तकरीर व राजस्थान की प्रसिद्ध कब्राल पाटियों द्वारा महफिल ए शमा का आयोजन होगा जिसमें सम्पूर्ण रात्रि तक बाबा की मान मनुहार की जाएगी। इसी प्रकार 19 अप्रैल शनिवार को रंग बिरंगे



कपड़ों में सज संवर कर विभिन्न वाहनों में सवार होकर बाबा के गीत गाते हुए हिन्दू मुस्लिम जायसीनों के जत्थे आएंगे। ईशा की नमाज के बाद में मिलाद ए पाक होगी इसके बाद में रात्रि 11 बजे बाद में महफिल ए शमा होगी इसमें भारत देश की

मशहूर कब्राल पाटियों द्वारा बाबा की मान मनुहार की जाएगी। इसी प्रकार 20 अप्रैल रविवार को सुबह 11 बजे सामूहिक कब्राल पाटियों द्वारा कूल की रस्म की अदायगी होगी इसी के साथ मे शहरी मेला सम्पन्न होगा।

आवश्यक नम्बर		रॉयल पत्रिका
विजली फॉन्ट के लिए		
टोल फ्री नंबर	180001805607	जलदाय कार्यालय
वांट्सएप नंबर	9414037085	फायर डिग्रेड
कस्टमर केयर	22030000	
आईटीआरएस	1912	
कचरा गाड़ी के लिए		
ग्रेटर	2747400	एंगुलैस
सिंक्लेज लीकेज	2607500	एसएमएस इमरजेंसी
हेरिटेज	2607500	महिला चिकित्सालय
टोल फ्री नंबर	14420	जाना हास्पिटल
		SDMH
		SMS ब्लड बैंक
		कल्याण ब्लड बैंक
पुलिस की मदद के लिए		
साइबर क्राइम	1930/2360094	घायल पशुओं के लिए
कंट्रोल रूम	2388435/3637/38	नगर निगम
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630	बर्ड बाइक
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098	हेल्प इन सर्कग्री
महिला हेल्पलाइन	1090	जनमंत्र ट्रस्ट
मुख्यमंत्री पोर्टल	181	पशु चिकित्सालय
		2747400
		9887345580
		8107299711
		7230055800
		2747400

अधिवक्ता संगठन भाइलाज ने किया ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन

कोटा, (रॉयल पत्रिका) ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर इस्टिस राजस्थान प्रदेश ईकाई द्वारा ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर, अधिवक्ता सदस्यों ने एकत्रित होकर ईद की मुबारकबाद दी और एक दूसरे के साथ त्योहार की खुशियां बाँटीं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली से आई संगठन की राष्ट्रीय समिति की सदस्या एडवोकेट सागरिका थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में बढ़ रहे वकीलों पर हमलों की विस्तृत जानकारी दी। राजस्थान की तर्ज पर दिल्ली प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाए जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी साझा किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वकील समुदाय के बगैर कोई क्रांति देश में संभव नहीं है, फासीवादी सरकारें इस समय देश में वकीलों की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। वकीलों पर



राजकीय दमन में बढ़ोतरी हुई है। इस मौके पर बोलते हुए कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट अंसार इंदौरी ने संगठन के कार्यों पर प्रकाश डाला। इस ईद मिलन कार्यक्रम में अधिवक्ता संगठन के सदस्यों और कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भाग लिया और एक दूसरे के साथ त्योहार की खुशियां मनाईं। इस अवसर पर, सदस्यों ने ईद की मुबारकबाद दी और एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द की भावना को मजबूत किया। कार्यक्रम के दौरान, सदस्यों ने

समाज में एकता और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की। हम सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं और कामना करते हैं कि यह त्योहार हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडवोकेट ज़ाकिर हुसैन, एडवोकेट रईस अहमद, एडवोकेट शेरबानो, असिस्टेंट प्रोफेसर सबरीना अंसारी, एडवोकेट बिलाल नूरी, एडवोकेट अनीस पठान, एडवोकेट शारिक सहित कई अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे।

पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति करें सुनिश्चित: जिला कलक्टर

- गर्मी के मौसम में आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित

बारों, (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने कहा कि आने वाले गर्मी के मौसम में लू से जनहानि रोकने, आमजन को राहत पहुंचाने और आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने हेतु सभी विभागों को सामंजस्य के साथ कार्य करना होगा। जिला कलक्टर ने गर्मी के मौसम में आमजन को पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी फील्ड अधिकारी एवं कर्मचारियों को मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से बुधवार को मिनी सचिवालय सभागार, कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।



जिला कलक्टर ने गर्मी के मौसम में आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर सभी उपखंड अधिकारियों, बिजली, पानी, चिकित्सा, पशुपालन, शिक्षा एवं महिला बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल और बिजली की सप्लाई सुचारू रखें ताकि आमजन को कोई समस्या नहीं हो। उन्होंने समर कंटीजेंसी प्लान को तुरंत स्वीकृत कराकर काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा जिले में निर्बाध विदूत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम

के अधिकारी बिजली आपूर्ति की सतत मॉनिटरिंग करें, और लाइनों में सुधार संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। जिला कलक्टर ने चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए कि अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाइयों एवं आइस पैक, आइस क्यूब आदि की उपलब्धता सहित कूलर, पंखे, छाया, पानी एवं बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

साथ ही, एम्बुलेंस में आपात स्थिति में उपचार हेतु आवश्यक दवा एवं उपकरण उपलब्ध हों। सभी चिकित्सा संस्थानों को लू प्रभावित व्यक्तियों के त्वरित उपचार के लिए तैयार रहने को कहा गया। उन्होंने पेयजल आपूर्ति के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर आवश्यकता अनुसार टैंकरों की व्यवस्था करने एवं समय पर पानी की सप्लाई, जल स्रोतों की सफाई एवं नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

दिए गए। मंडी सचिव को मंडियों में किसानों के लिए छाया, पेयजल और प्राथमिक उपचार की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों की पहचान करें और व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्यों की टीमों बनाकर हीट वेव से बचाव हेतु किए गए उपायों की जमीनी स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, एडीएम (कार्यवाहक) अनिल चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी, पीएमओ डॉ. नरेंद्र मेघवाल, एसई एनएस बिलोटिया, संयुक्त निदेशक सतीश लहरी सहित सभी उपखंड अधिकारी, विभागीय अधिकारी एवं तकनीकी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जिला कलक्टर ने बामनवास में मनरेगा कार्यों का किया निरीक्षण

सवाई माधोपुर, (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने बुधवार को पंचायत समिति बामनवास की ग्राम पंचायत डाबर एवं बाढ़ मोहनपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत संचालित विभिन्न कार्यों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने कार्य स्थलों पर श्रमिकों की उपस्थिति, उनके लिए छाया एवं पेयजल, मेडिकल जैसी मूलभूत सुविधाओं, कार्य की गुणवत्ता, निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रगति तथा संपूर्ण कार्य प्रणाली की बारीकी से जांच की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। जिला कलक्टर ने विकास अधिकारी बामनवास को निर्देश दिए कि मनरेगा के अंतर्गत



संचालित सभी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा श्रमिकों के समय पर भुगतान की सुनिश्चितता हो। उन्होंने कहा कि मनरेगा न केवल ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है, बल्कि इसके माध्यम से ग्राम्य बुनियादी ढांचे का भी विकास होता है, कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत

डाबर में मेट को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को प्रदान किए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सुनील कुमार मीना, विकास अधिकारी नरेंद्र कुमार मीना, तहसीलदार बामनवास, एमआईएस मैनेजर थानवेद अग्रवाल, जीटीए लोकेश शर्मा, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पेयजल, लू-तापघात एवं एमएसपी पर खरीद को लेकर बैठक

- अंतिम छोर के घरों में जाकर जल दबाव की जांच करने के निर्देश

हनुमानगढ़, 9 रॉयल पत्रिका)। ग्रीष्म ऋतु की गंभीरता, आगामी नहरबंदी, पेयजल आपूर्ति, हीटवेव से बचाव तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल खरीद की व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर काना राम की अध्यक्षता में बुधवार जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम ग्राम पंचायत स्तर पर निरीक्षण करें, अंतिम छोर के घरों में जाकर जल दबाव की जांच करें तथा निरीक्षण की रिपोर्ट साझा करें। साथ ही, बस स्टैंड व अस्पतालों में प्याऊ, सरकारी कार्यालयों में पक्षियों के लिए परिडे तथा जोहड़ों व पशु खेलियों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।



ग्रीष्मकालीन पेयजल आपूर्ति के लिए पुख्ता प्रबंध
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता विजय वर्मा ने बताया कि जिले के 7 शहरों में से 5 शहर इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के पेयजल से लाभान्वित हैं, जबकि टिब्बी भू-जल पर आधारित है। वर्तमान में 5 शहरों में 24 घंटे और नोहर व रावतसर में 48 घंटे के अंतराल से जलापूर्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के 1323 गांव 308 जल योजनाओं से जुड़े हैं, जिनमें जल मांग के अनुसार आपूर्ति की जा रही है।

हाइड्रो जल नहर प्रणाली से जुड़ी नोहर व भादरा की योजनाओं पर भी 25 मार्च से 15 मई तक पूर्ण नहरबंदी रहेगी। जल परिवहन हेतु टैंडर प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यनिर्देश जारी कर दिए गए हैं। पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष (01552-260553) की स्थापना कर दी गई है।

हीटवेव से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनील शर्मा ने जानकारी दी कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर लू-तापघात से बचाव हेतु प्रशिक्षण, बेड आरक्षण, कूलर पंखे, दवाइयों व आपातकालीन किट्स की व्यवस्था की जा चुकी

है। नरेगा साइट, स्कूलों, ईट भट्टों और रेन बसेरों का निरीक्षण करने हेतु चिकित्सा अधिकारियों को पाबंद किया गया है। आमजन को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। एम्बुलेंस स्टाफ को टाको मेथड का प्रशिक्षण और आईस पैक बॉक्स रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

एमएसपी पर फसल खरीद की निगरानी के निर्देश
जिले में 58 कृषक केंद्रों पर एमएसपी पर फसल की खरीद की जा रही है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि तहसीलदार व नायब तहसीलदार साप्ताहिक निरीक्षण करें। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी, छाया और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहे। पटवारी व कृषि पर्वक्षकों की ज़रूरी रोटेशन आधार पर लमाई जाए और फसल का उठाव सही ढंग से सुनिश्चित किया जाए। बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वरुंअल माध्यम से शामिल हुए।

कांग्रेस सेवादल ने अम्बेडकर जयंती पर निकले जुलूस का किया भव्य स्वागत



शब्बीर हुसैन बारों, (रॉयल पत्रिका)। कांग्रेस सेवादल ज़िला मीडिया प्रभारी पार्षद ज़ाकिर खान ने बताया कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर बारों शहर में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसका कांग्रेस सेवादल ने बंक के आगे शाहबाद रोड़ पर स्वागत किया। इस अवसर पर सेवादल ज़िला अध्यक्ष शिवविकर यादव ने कहा डॉ. अम्बेडकर, जिन्हें हम बाबासाहेब के नाम से भी जानते हैं, वह एक प्रसिद्ध न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प ले कि उनके द्वारा बनाए हुए संविधान के आधार पर देश में अपना जीवन जिए, ना तो संविधान का उल्लंघन करें, न ही संविधान के विपरीत चले। इस अवसर पर डीसीसी उपाध्यक्ष अशरफ देशवाली, नगर अध्यक्ष रोहित गुर्जर, सेवादल उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा भूलहेड़ी, विजय बैरवा, पार्षद ललित गुर्जर, शिवराज मीना, राजेंद्र यादव, जगदीश महावर, राकेश गौड़, पवन पांचाल, जुगल पांचाल, बहादुर सुमन, नरेंद्र यादव, आशाराम बैरवा, रहीम खान, रामप्रकाश बैरवा, अजय सेनी, सुरेश भांड आदि मौजूद रहे।

विवेकानंदपुरम को मिली नई सौगात



सवाई माधोपुर, (रॉयल पत्रिका)। कृषि, उद्यमिकी एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को सवाई माधोपुर के रणथम्भौर रोड़ स्थित विवेकानंदपुरम में 32.05 लाख रुपये की लागत से सड़क मरम्मत एवं नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। निर्माण कार्य से ग्राम हिम्मतपुरा, नयापुरा एवं समीपस्थ विद्यालयों के विद्यार्थियों और ग्रामीणों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी। निर्माण के पूर्ण होने के पश्चात इन क्षेत्रों के नागरिकों को मुख्य मार्ग से सुगम और सुरक्षित संपर्क मिलेगा, जिससे विशेष रूप से विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सड़क और नाली

निर्माण कार्य क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग रही है, जिसे आज पूरा करते हुए मुझे अत्यंत संतोष हो रहा है। यह विकास कार्य केवल आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं है, बल्कि यह हमारे बच्चों के सुरक्षित भविष्य और आमजन के सुगम जीवन की दिशा में एक ठोस कदम है। आने वाले समय में हम ऐसे और भी कार्यों को गति देंगे, जिससे हर गांव, हर गली विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। इस अवसर पर तहसीलदार विनोद शर्मा, यूआईटी एक्सईएन अमित गोयल, पूर्व सभापति राजेश गोयल, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष दीपक मीणा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

जिला कलक्टर ने किया बामनवास उपखंड, तहसील एवं थाना का औचक निरीक्षण - थाने में व्यवस्थाओं का लिया जायजा



सवाई माधोपुर, (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने बुधवार को बामनवास क्षेत्र के उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं थाना का निरीक्षण कर विभागीय कार्यप्रणाली, नागरिक सेवाओं की स्थिति एवं कानून-व्यवस्था का जायजा लिया। **उपखंड कार्यालय में लिया प्रकरणों का फीडबैक**- निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने उपखंड अधिकारी से रूपांतरण, आईटीआई, नामांतरण, सीमाज्ञान, कन्वर्जन सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उपखंड न्यायालय में 10 वर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि इन मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि नागरिकों को समय पर राहत मिल सके।

उपस्थिति और कार्यप्रणाली- तहसील कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने कर्मचारियों की उपस्थिति पंजीका की जांच की, सीमाज्ञान के प्रकरण, ऑनलाइन कन्वर्जन, संपर्क पोर्टल, रिस्वीवी प्रकरणों, नामांतरणों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व कार्यों की गति और सेवा वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने पर ज़ोर दिया।

थाना निरीक्षण में देखी व्यवस्थाएं- बामनवास थाना निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने मालखाना, कम्प्यूटर कक्ष, बंदीगृह का निरीक्षण किया। उन्होंने मालखाने में जब्त वस्तुओं की सुव्यवस्थित रख-रखाव एवं उनके सुरक्षित संधारण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कम्प्यूटर कक्ष की कार्यप्रणाली, एफआईआर पंजीकरण और ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली का अवलोकन किया।

बंदीगृह की स्थिति और सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुनील कुमार, तहसीलदार बामनवास, डिप्टी बामनवास, थाना अधिकारी बामनवास सहित अन्य अधिकारी अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में आमुरवीकरण प्रशिक्षण सम्पन्न

- जिला कलक्टर रामावतार मीणा ने कहा महिला कर्मिकों के लिए उपयोगी साबित होगा प्रशिक्षण

झुंझुनू, (रॉयल पत्रिका)। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बुधवार को सूचना केन्द्र सभागार में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में आमुरवीकरण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए जिला कलक्टर रामावतार मीणा ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण महिलाओं के लिए उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का शोषण या भेदभाव नहीं हो इसके लिए जिला प्रशासन एवं कार्यालयों में बनी समितियां नियमित मॉनिटरिंग करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। महिला अधिकारिता के उप निदेशक विष्णु न्यौला ने स्थानीय समिति की आवश्यकता बनने के कारण व इसके कानून के बारे में



विस्तार से बताया। आमुरवीकरण प्रशिक्षण में रिसोर्स पर्सन पीयूष पोद्दार व समीक्षा झा मार्या फेरल फाउंडेशन दिल्ली ने विस्तार से कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न संबंधित सभी कानून, जांच, शिकायत के प्रकार, जवाब देही, निगरानी और निवारण के बारे में बताया। प्यारेवाल दुकिया ने सरकारी के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी इस प्रकार के प्रशिक्षणों की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान जिला स्तरीय समिति की सदस्या के

रूप में अति. कोषाधिकारी प्रेरणा कालेर, प्रियंका लाम्बा, अति. पुलिस अधीक्षक हेमन्त कुमार, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता महेन्द्र झाड़ाडिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक डॉ. पवन पूनियां, जनसम्पर्क अधिकारी हिमांशु सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी आंतरिक समाधान समिति के अध्यक्ष, आंतरिक समिति, स्थानीय समिति, ब्लॉक लेवल पर नामित सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया।

जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग की बैठक आयोजित

- बाल विवाह को रोकने के लिए संयुक्त अभियान

बारों, (रॉयल पत्रिका)। जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि विभाग की जिला स्तरीय बैठक मिनी सचिवालय में एडीएम दिव्यांशु शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। एडीएम ने कहा कि बाल विवाह के मामले में अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रम, अभियान चलाकर बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया जाए व उससे होने वाले दुष्परिणाम के बारे में स्कूल, छात्रावास, ग्राम पंचायत, ऑनलाइन बाड़ी केन्द्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसम्पर्क कर बाल विवाह को रोकने के लिए कार्यशाला व कार्यक्रम आयोजित किए जाए। उन्होंने बाल विवाह का आयोजनकर्ता (रिश्वेतदार, बारातियों, पंडित, हलवाई, टेन्ट व बैंड बाजा आदि) व अन्य जुड़े लोगों से बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने में सहयोग प्रदान करने की अपील की। साथ ही जिले में बाल विवाह के मामलों की संख्या को शून्यकरण करने का निर्णय लिया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ओमप्रकाश मेहता ने बताया कि आखातीज (अक्षय तृतीया) पर होने



वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में बाल विवाह पर सम्बन्धित विभाग व जिले में संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 निगरानी रखकर, बिना विलम्ब के सम्बन्धित अधिकारी व बाल कल्याण समिति को मौके पर सूचना कर अवगत करा सकते हैं। बाल अधिकारिता व सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ने कहा कि जिले में कहीं पर भी बाल विवाह के सूचना मिलने व बाल विवाह होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दे और प्रशासन कि मदद से बाल विवाह रुकवाने में मुख्य प्रयास करें। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 समन्वयक कोऑर्डिनेटर ने बाल निषेध अधिनियम 2006, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और

संरक्षण) अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अनुरूप बाल विवाह रोकने के विषय पर जाणकारी दी। बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, सहायक निदेशक शुभम नागर, अध्यक्ष ओमप्रकाश मेहता व बाल कल्याण समिति सदस्य आफाक अहमद, बाल अधि. विभाग संरक्षण अधिकारी लोकेश सेन, एसपीओ कोमल प्रसाद, महिला अधिकारिता विभाग पुष्पा शर्मा, चाइल्ड हेल्प लाईन से मनीश राठौर, प्रियंका खत्री, सुरभि गौतम, श्वेता अदलकवा, शिशु गृह से कीर्ति चतुर्वेदी, रेखा शर्मा, राजेश कुमार मीणा, जगदीश सुमन, सृष्टि सेवा संस्थान से विजय कुशवाहा, कमल प्रजापति आदि उपस्थित रहे।

7 वां खेलो इण्डिया यूथ गेम्स 4 से 15 मई तक

सवाई माधोपुर, (रॉयल पत्रिका)। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 7 वां खेलो इण्डिया यूथ गेम्स-2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई, 2025 तक बिहार में कुल 28 खेलों (20 व्यक्तिगत एवं 8 टीम गेम) में किया जा रहा है। जिसके तहत राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा चयन स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा।

जिला खेल अधिकारी अब्दुल वहीद ने बताया कि बालक-बालिका वर्ग के लिए वॉलीबॉल एवं मलखंब खेल 17 अप्रैल को प्रातः 8 बजे एम.एस.एस. स्टेडियम जयपुर में, फुटबॉल खेल बालिका वर्ग 17 अप्रैल को प्रातः 8 बजे बी.वी.बी. विद्या आश्रम स्कूल, केएम मुन्शी मांग ओटीएस के सामने जयपुर में खेला जाएगा। वहीं 18 अप्रैल को प्रातः 8 बजे

रबी बालक-बालिका वर्ग चोगान स्टेडियम जयपुर में तथा 19 अप्रैल को प्रातः 8 बजे कबड्डी खेल बालक-बालिका वर्ग के लिए चोगान स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा। इसी प्रकार 21 अप्रैल को प्रातः 8 बजे बॉस्केटबॉल बालक के लिए एवं सेकप-तकरा बालक-बालिका वर्ग के लिए एस.एम.एस. स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा।



देश की शीर्ष अदालत ने की ऐतिहासिक टिप्पणी, भाषा कोई धर्म नहीं होती, यह संवाद का एक माध्यम

एजेसी नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी में कहा कि उर्दू भाषा भारतीय संस्कृति की आत्मा का हिस्सा है और इसे किसी भी रूप में विदेशी करार देना सरासर गलत है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में पातुर नगर परिषद भवन पर उर्दू साइनबोर्ड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने इसे हिंदुस्तानी तहजीब का बेहतरीन नमूना बताया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

उर्दू की ऐतिहासिक भूमिका रही

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाया

अदालत ने कहा कि उर्दू भी भारत की ही उपज है, और यह गंगा-जमुनी तहजीब का जीवंत मिसाल है।

सुप्रीम कोर्ट का सवाल, साइनबोर्ड पर उर्दू से चिढ़ क्यों? यह तो गंगा जमुनी तहजीब का आधार, इसे 'विदेशी' करार देना सरासर गलत

अकोला जिले में पातुर नगर परिषद भवन पर उर्दू साइनबोर्ड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया



यह या नानला?

पूर्व पार्श्व की याचिका में पातुर नगर परिषद भवन के उर्दू साइनबोर्ड को गैरकानूनी बताया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022 के तहत उर्दू का प्रयोग वर्जित है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा है।

उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं
अदालत ने इस धारणा को बिलकुल गलत बताया कि उर्दू भारत के लिए विदेशी है। उर्दू एक इंडो-आर्यन भाषा है, जो भारत में ही जन्मी और विकसित हुई। यह संवाद की जरूरतों से निकली और फारसी, संस्कृत, हिंदी जैसी भाषाओं से घुलती-मिलती रही। फैसले में यह भी कहा गया कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की दिशा में प्रयास ही रहे थे।

भाषा से डरो मत उसे गले लगाओ

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद साहित्यिक भाषा में कहा कि भाषा धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वह किसी समुदाय की विरासत होती है, उसकी आत्मा होती है। अदालत ने यह भी कहा कि हमें अपनी विविधता में सौंदर्य देखना चाहिए, क्योंकि भारत की असली पहचान उसकी भाषाई विविधता में ही छिपी है।

खबर संक्षेप

बर्क का न्यायिक जांच आयोग में बयान दर्ज
लखनऊ। संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल के मामले में आरोपी सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क बुधवार को न्यायिक जांच आयोग के सामने बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ पहुंचे। आयोग ने उन्हें और एक विधायक के बेटे को आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए समन भेजा था। बर्क ने कहा, जबवा देना मेरा कर्तव्य है।

मणिकर्णिका में रील के चक्कर में बही महिला
मणिकर्णिका। उत्तराखण्ड के मणिकर्णिका में रील बनाते वक्त एक महिला भागीरथी नदी में बह गई। हादसे के वक्त महिला की मासूम बच्ची 'ममी-ममी...' चिल्लाती रही। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। 14 अप्रैल को मणिकर्णिका में महिला नदी में डूब गई। नेपाली मूल की विशेषता घाट पर गई थी। रील के चक्कर में नदी में डूब गई।

घर गिराने के बाद नगर निगम ने मांगी माफ़ी
नागपुर। सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि कोई भी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया अपनाए बगैर नहीं की जा सकती। मगर नागपुर नगर निगम ने दंगा आरोपी फहीम खान का दो-मंजिला मकान गिरा दिया। नगर निगम ने बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच के सामने माफ़ी मांग ली है।

त्रिनेत्र गणेश मंदिर में बच्चे को ले गया बाघ
सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दोपहर 3 बजे दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मच गया, जब एक बाघ जंगल से निकलकर आया और 6 साल के मासूम को उठाकर ले गया।

जमीन खरीद मामले में दूसरे दिन ईडी के सामने पहुंचे वाड़ा, बोले राजनीतिक 'प्रतिशोध' के तहत की जा रही कार्रवाई, सब वक्त का खेल, समय बदलेगा

एजेसी नई दिल्ली

उनके और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही

गुरुग्राम भूमि सौदे के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को भी रॉबर्ट वाड़ा से पूछताछ की। लगातार दूसरे दिन पूछताछ से पहले जानेमाने कारोबारी ने बुधवार को कहा कि वह इन सबके लिए बहुत मजबूत है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए एक सियासी कार्ड भी पोस्ट किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। हमारे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई की जा रही है। सब वक्त का खेल है, समय बदलेगा। उन लोगों को भी झेलना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं देश छोड़कर भागने वाला नहीं हूँ। मैं सभी सवाल का जवाब दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी चाहें उतनी एजेंसियां का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जब इसकी जांच हुई तो प्रशासन ने पाया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। खट्टर जी ने मुझे उसी मामले में क्लीन चिट दे दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 7 साल बाद फिर मुझे पूछताछ क्यों हो रही है?



गुरुग्राम भूमि सौदे के मामले में बयान दर्ज

मैं देश छोड़कर भागने वाला नहीं
वाड़ा ने कहा कि वह निर्दोष है और सत्य की जीत होगी। वाड़ा ने पत्रकारों पर पोस्ट किया कि मेरे जन्मदिन के सप्ताह के दौरान की जा रही सेवाएं कुछ दिनों के लिए रोक दी गई हैं। मैंने बुजुर्गों को मोहन कराने और बच्चों को उपहार देने का जो योजना बनाई है, उन्हें मैं तब तक जारी रखूंगा, जब तक कि सरकार मुझे अच्छे काम करने और अपराधियों के प्रति उन्नत अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में बोलने से नहीं रोकती।

ये झूठा मामला : गहलोत
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर कहा, देश में इस तरह का माहौल बनना जा रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। भाजपा बार-बार लोकतंत्र की हत्या करने के काम करते हैं। ये बहुत खतरनाक है। ईडी पहले भी जांच कर चुकी है। क्लीन चिट भी मिल चुकी है। अब फिर ये मामला शुरू कर दिया, ये झूठा मामला है, इसमें कोई दम नहीं है।

ईडी ने पहली बार की ऐसी कार्रवाई
यह संभवतः पहली बार है, जब ईडी का धनशोधन मामला अधीनस्थ अदालत द्वारा एक निजी शिकारत का रिकॉर्ड लेने और उसके बाद मुख्यमंत्री शुरू करने के लिए आरोपियों को समन जारी करने से उपजा है। एजेंसी आमतौर पर पीएमएसएफ के तहत अधिवक्ता की अनुसूची ए और बी में सूचीबद्ध अपराध का रिकॉर्ड लेती है।

एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा विरोधियों को दबाया जा रहा

ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड से जुड़े केस में चार्जशीट दाखिल की है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने देशभर में प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि एजेंसियां विरोधियों को दबाने के लिए दुरुपयोग कर रही हैं। कांग्रेस राज्य मुख्यालयों में ईडी कार्यालयों के सामने, राज्यों में जिला स्तर पर केंद्र के कार्यालयों के सामने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद स्थिति को देखते हुए पुलिस भी वहां पहुंच गई है और कई लोगों को हिरासत में ले लिया है।

ये बोले कांग्रेस नेता

एजेंडा सिर्फ विपक्ष को परेशान करना: प्रतापगढ़ी
केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में अब पार्टी सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी के जरिए लडाई को कोर्ट तक ले जाया गया है, उसकी मंशा सिर्फ विपक्ष को परेशान करने की है। गुजरात में खर होता है, राहुल गांधी मोडसा पहुंचते हैं और यहां चार्जशीट दाखिल हो जाती है। आप कोनेलॉजी समझिए।

मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं: वाड़ा
वाड़ा ने आरोप लगाया कि संघीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, 'मेरे पहले दिन स्वालों के जवाब दिए हैं, उन सभी के जवाब फिर से देने पड़े हैं। कोई गुद्दा ही नहीं है।'

माजपा ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता को घेरा, मनाया शहीद दिवस हम कारगर हिंदू नहीं हैं, हम स्वामी विवेकानंद के हिंदू हैं: सुवेंदु

रॉयल पत्रिका ममता हिंदुओं की बलि चढ़ाना चाह रही

मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए हिंदू परिवार को श्रद्धांजलि देते हुए, भाजपा ने कोलकाता में राज्य विधानसभा के बाहर हिंदू शहीद दिवस मनाया। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने पार्टी विधायकों की सभा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू आबादी भावुक है, यह दुःखद है। पूरा राज्य सड़कों पर है और हिंदू शहीद दिवस मना रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता को पद छोड़ देना चाहिए। उन्हें जेल जाना चाहिए। हम कारगर हिंदू नहीं हैं, हम स्वामी विवेकानंद के हिंदू हैं। भाजपा विधायक शंकर घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं।



माजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बीएसएफ, केंद्रीय बलों, वदीधारी बलों, सशस्त्र बलों को गाली देना टीएसपीसी की संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। वे सीमा, सीएसपीएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, एनएसए, एनआईए और सभी एजेंसियों को गाली देते हैं और यह उनकी सुरक्षा का गंवा है। न्यायपालिका ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल तैनात किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें बंगाल पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, कि ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद से यह राजनीतिक हिंसा के लिए संस्थान हो गई है। यह केवल दंगाइयों को बचाने और उनका बचाव करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह राज्य प्रयोजित हिंसा है, हिंदुओं पर राज्य प्रयोजित हिंसा हमले हो रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने बनर्जी पर निशाना साधते हुए पूजा कि क्या उनकी सरकार बुनियादी मानवीय मूल्यों के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील हो गई है।

नासिक में धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चला मीड और पुलिस में भिड़ंत 21 घायल, 15 लोग अरेस्ट



एजेसी नासिक

महाराष्ट्र के नासिक में धार्मिक स्थल पर बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल हो गया। धार्मिक स्थल को गिराने पर गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इसमें 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ ने तीन पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले छोड़े और स्थिति को नियंत्रण में किया। 15 लोगों को हिरासत में लिया है। अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शहर के काठे गली इलाके में स्थित अनधिकृत सतपीर बाबा दरगाह को हटाने का आदेश दिया था। नासिक के पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक सतपीर दरगाह के टूटने में मंगलवार रात को बांके को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उस्मानिया चौक पर भीड़ जमा हो गई।

उपद्रवियों के पथराव में कई वाहन क्षतिग्रस्त

पुलिस अधिकारियों ने भी उन्हें शत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी। उपद्रवियों ने पथराव किया और कुछ वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। हमले में तीन पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दरगाह को सुबह ध्वस्त कर दिया गया। सड़कों को 57 मीटर साइकिलें जकड़ की गई हैं। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है।

50 एनएमसी कर्मियों ने की कार्रवाई

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान लगभग 50 एनएमसी कर्मियों ने 4 मिट्टी खोदने वाली मशीनों, 6 ट्रकों और 2 डंपरों से मलबा हटाया। इससे पहले फरवरी में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम ने दरगाह के निकट कई अनधिकृत संरचनाओं को हटा दिया था। नासिक सेंट्रल की विधायक देवयानी फरांडे ने भी कहा था कि पूरे स्थल को साफ किया जाना चाहिए।

सैनटरी कचरा का निपटान देशभर में एक बड़ी चुनौती महाराष्ट्र का कराड एक रोल मॉडल के रूप में उभरा और उसने मानक स्थापित किया

यहां प्रतिदिन लगभग 350 किलोग्राम जमा हो रहा

एजेसी कराड

महाराष्ट्र के कराड में अस्पतालों, क्लीनिकों, घरों और अन्य स्थानों से प्रतिदिन लगभग 350 किलोग्राम सैनटरी कचरा जमा किया जाता है। भारत में सैनटरी कचरे का प्रबंधन बड़ी चुनौती है, इसका अनुचित तरीके से निपटान होने से पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं। सतारा जिले का एक छोटा शहर कराड इस मुद्दे से निपटने में एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है। सैनटरी और बायोमैडिकल कचरे के शत-प्रतिशत पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण के साथ, कराड ने प्रभावी और टिकाऊ कचरा प्रबंधन के लिए एक मानक स्थापित किया है।

नारिदाओं ने भी सहयोग किया



सैनटरी अपशिष्ट निपटान और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई। स्कूलों को सैनटरी पैड वॉशिंग मशीन और निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

आवृत्त और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक बखाना जारी कर इसके बारे में बताया है। कराड नगर परिषद (केएससी) ने महिलाओं के साथ मिलकर काम किया, जिससे महिला बल्लियों का गठन हुआ, जिन्होंने आवृत्त क्षेत्रों में उचित सैनटरी अपशिष्ट निपटान और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई। स्कूलों को सैनटरी पैड वॉशिंग मशीन और निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

कांग्रेस ने किया केंद्र पर बड़ा हमला, बोले- सिंघवी और जयराम 'मेक इन इंडिया' फेल, ये 'फेक इन इंडिया' चला रहे

रॉयल पत्रिका

नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में आई तेजी ने राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कथित रूप से फंसाने के खिलाफ देशभर में ओटोलन किए, वहीं पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने मोर्चा संभाला। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस को प्रेरित किया। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम दर्ज करने को राजनीतिक प्रतिशोध और झूठा नैरेटिव करार दिया है।

पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को वास्तविक अर्थों में प्रतिशोध बताया। उन्होंने कहा कि ईडी एक फर्जी नैरेटिव बना रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सिंघवी ने तर्क दिया कि एजेएल एक पुरानी कंपनी है, जो सफल नहीं हो सकी। कांग्रेस ने इसे 50 साल में अलग-अलग समय पर ऋण दिए और इसमें कोई अवैधता नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा था कि यह मामला सरकार द्वारा

अतिसंवेदनशील बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य राजनीतिक विरोधियों को परेशान करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सोनिया और राहुल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी, जो उनके लिए बड़ी राहत थी। जयराम ने इस मामले को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध और डराने-धमकाने की नीति करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई देश का ध्यान आर्थिक संकट, अमेरिकी टैरिफ, चीन और बांग्लादेश के साथ तनाव जैसे मुद्दों से हटाने के लिए की जा रही है। रमेश ने इसे फर्जी नैरेटिव बताया और कहा, जब 'मेक इन इंडिया' फेल हो गया, तो ये लोग 'फेक इन इंडिया' चला रहे हैं।

नेशनल हेराल्ड मामला

नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसकी स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी, एसाइनिंग लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित होता था। 2008 में वित्तीय संकट के कारण यह बंद हो गया। इस मामले में आरोप है कि कांग्रेस ने एजेएल को ऋण दिया, जिसे बाद में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआई) ने अपने कब्जे में ले लिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो यंग इंडियन में 38-38 फीसदी शेयरधारक हैं, पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। ईडी का दावा है कि एजेएल की 661 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया, जिसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में संपत्तियां शामिल हैं। 11 अप्रैल 2025 को, ईडी ने इन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की, और 15 अप्रैल 2025 को सोनिया गांधी (आरोपी नंबर 1), राहुल गांधी (आरोपी नंबर 2) और अन्य के खिलाफ प्रिचेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत चार्जशीट दायर की। विशेष अदालत इस चार्जशीट पर 25 अप्रैल 2025 को सुनवाई करेगी।

स्पेशल: वर्ल्ड लिवर डे, 19 अप्रैल

मौजूदा दौर में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत डाइट हैबिट के कारण लोगों में लिवर के रोगग्रस्त होने की आशंका बढ़ गई है। इससे कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिन्हें इग्नोर करना घातक हो सकता है। ऐसे में उन कारणों को समझना बहुत जरूरी है, जो लिवर को बीमार कर देते हैं। साथ ही इनसे बचने के उपाय और उपचार के बारे में भी जानिए।

लिवर हेल्थ को कभी ना करें इग्नोर



इन बातों पर दें ध्यान

- डाक्टर की सलाह के बगैर पेनकिलस या फिर एंटीबायोटिक्स लेना लिवर को सेहत के लिए नुकसानदेह है।
- एंटीडिप्रेसेंट मेडिसिंस (अक्सादरोधी दवाएं) के भी लिवर पर साइड और अपडर इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए ऐसी दवाओं का सेवन मनोरोग विशेषज्ञ के परामर्श से करें।
- दिन भर विभिन्न खाद्य पदार्थों के जरिए लगभग 3 से 5 ग्राम नमक (चाय की छोटी चम्मच की मात्रा भर) का सेवन किया जा सकता है। नमक का अधिक सेवन लिवर में सूजन के खतरों को बढ़ा देता है।
- ट्रांस फैट्स के सेवन से बचें। जब तेल में खाद्य पदार्थों को बार-बार तला जाता है तो ऐसे खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट्स की मात्रा बढ़ जाती है। ट्रांस फैट्स से निर्मित खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त कैलोरीज होती है, जिससे वजन तेजी से बढ़ता है और ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से कालांतर में लिवर की कोशिकाओं पर वसा की परत संचित होने लगती है, जिससे लिवर में सूजन संभव है।
- अत्यधिक शुगर और 'कृत्रिम स्वीटनर्स' युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें, क्योंकि ये कालांतर में लिवर के लिए नुकसानदेह हैं।



डॉक्टर एडवाइस

डॉ. राजनी सुंदर
चेयरमैन-गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट
मेदांता डि मेडिसिटी, गुडगांव

हमारे पाचन तंत्र का 'पावर हाउस' है यकृत (लिवर या जिगर), जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकाल बाहर करने का माध्यम भी है। शरीर के इतने महत्वपूर्ण अंग के स्वास्थ्य को बरकरार रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यहां दिए गए लक्षणों में से कुछ लक्षणों से पीड़ित हैं और आपको राहत नहीं मिल रही है, पेट की समस्या जारी है तो इस स्थिति में डॉक्टर से परामर्श करने में देर न करें।

बीमार लिवर के कुछ सामान्य लक्षण

- खाने का मन ना करना, भूख धीरे-धीरे कम होते जाना।
- अकसर पेट में दर्द या एंठन महसूस होना।
- पेट में अकसर सूजन होना।
- सामान्य डाइट के बावजूद वजन का कम होते जाना।
- पैरों में सूजन होना।
- बिना किसी संक्रमण के अकसर बुखार होना।
- बगैर श्रम किए हमेशा थकावट महसूस करना।
- पीलिया (जॉण्डिस) के लक्षण दिखना जैसे आंखों, नाखूनों और त्वचा के रंग का पीला होना।
- जो मिचलाना और अकसर दस्त होना।

लिवर की गंभीर बीमारियां

लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और फैटी लिवर को प्रमुख बीमारियों में शुमार किया जाता है।

बहुत खतरनाक है लिवर कैंसर

लिवर से संबंधित कोई भी बीमारी जो लंबे समय से जारी हो, वह लिवर कैंसर बन सकती है। कारण: लिवर कैंसर होने के तीन प्रमुख कारण हैं- हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। फैटी लिवर डिजीज। एल्कोहलिक लिवर डिजीज।

रोकथाम: अगर लिवर कैंसर का कारण हेपेटाइटिस बी है, तो इसको रोकथाम के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। अगर हेपेटाइटिस बी के कारण लिवर में संक्रमण है तो शुरुआती दौर में इसका इलाज संभव है। हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका इलाज संभव है। अगर एल्कोहलिक लिवर डिजीज के कारण लिवर कैंसर पनप चुका है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले शराब पीना बंद करना जरूरी है, क्योंकि यह समस्या काफी दिनों तक अत्यधिक शराब पीने के कारण होती है।

लिवर कैंसर का इलाज: सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि लिवर कैंसर की अवस्था (स्टेज) क्या है। ऐसे कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में सर्जरी भी कर सकते हैं या फिर मरीज को स्थिति के मद्देनजर लिवर ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। अगर कैंसर स्टेज 3 या 4 में है तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के जरिए इलाज किया जाता है।

लिवर सिरोसिस

कारण: उपरोक्त वर्णित लिवर कैंसर के जो कारण हैं, वे लिवर सिरोसिस के संदर्भ में भी लागू होते हैं। यही बात लिवर सिरोसिस की रोकथाम के संदर्भ में भी लागू होती है।

लक्षण: खून की उल्टी होना, आंत में रक्तस्राव होना, पेट में पानी भरना लिवर सिरोसिस के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा मरीज का अतार्किक बातें करना, जिसे सहज भाषा



में मरीज का 'गफलत में जाना' भी कहते हैं। मरीज बेहोश भी हो सकता है। इसके अलावा मरीज के रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर भी गिर जाता है।

रोकथाम-इलाज: मरीज का अतिशय शराब छोड़ना जरूरी है। इसके अलावा लिवर सिरोसिस की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति का इलाज उसकी शारीरिक स्थिति और लक्षणों के आधार पर किया जाता है। लिवर सिरोसिस को दवाओं से नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है।

डाइट हैबिट से जुड़ा फैटी लिवर

अगर लिवर में 5% से ज्यादा वसा कोशिकाएं (फैट सेल्स) संचित हो जाती हैं तो इस स्थिति को फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। फैटी लिवर का पता पेट के अल्टासाउंड से लगता है। फैटी लिवर के दो प्रकार हैं- एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज।

एल्कोहलिक फैटी लिवर काफी दिनों तक अत्यधिक शराब पीने से होता है, जिसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले शराब छोड़ना होता है। इसके बाद मरीज को दवाएं भी दी जाती हैं।

लक्षण: दोनों प्रकार की फैटी लिवर की समस्याओं में अकसर पेट से संबंधित तकलीफें महसूस होती हैं। जैसे पेट दर्द, दस्त होना, पेट फूलना, गैस बनना, बदहजमी, भूख कम लगना और कब्जियत आदि।

अनहेल्दी लाइफस्टाइल का नतीजा: नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर के ज्यादातर मामले अनहेल्दी डाइट, नियमित रूप से व्यायाम या शारीरिक श्रम न करने और मोटापे के कारण बढ़ते हैं। जो लोग जंक फूड्स और अत्यधिक चिकनाई युक्त आहार को प्रतिदिन या अकसर ग्रहण करते हैं, उनमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इन दिनों युवा वर्ग भी

बड़े पैमाने पर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर समस्या से ग्रस्त हो रहा है। उनमें बढ़ती इस बीमारी का एक प्रमुख कारण फैटी फूड्स, फास्ट फूड और जंक फूड्स को अपने खान-पान में वरीयता देना है।

इनको है ज्यादा रिस्क: जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं या फिर जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर है, उनमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर होने का खतरा ज्यादा होता है। मोटापे से ग्रस्त जिन लोगों के पेट पर शरीर के अन्य भागों की तुलना में कहीं ज्यादा चर्बी संचित होती है, उन्हें फैटी लिवर होने का जोखिम ज्यादा है। मधुमेह ग्रस्त लोगों को फैटी लिवर का जोखिम ज्यादा रहता है। इसलिए ऐसे लोगों को ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखना चाहिए। जिन लोगों के रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर ज्यादा है, उनमें भी फैटी लिवर का जोखिम ज्यादा होता है। इस संदर्भ में डॉक्टर से परामर्श लेकर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं।

रोकथाम-इलाज: फैटी फूड्स और जंक फूड्स से जहां तक संभव हो परहेज करें। शारीरिक स्थिति और उम्र के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम करें। बेहतर रहेगा कि आप व्यायाम करने से पूर्व इस संदर्भ में फिटनेस एक्सपर्ट और अपने डॉक्टर से परामर्श लें। जो लोग मोटापे के कारण फैटी लिवर की समस्या से ग्रस्त हैं, अगर वे अपने वजन को खान-पान और व्यायाम के जरिए 7 से 10% तक कम कर लेते हैं तो उन्हें काफी राहत मिल सकती है। अगर जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिलते तो फैटी लिवर से छुटकारा पाने के लिए दवाएं दी जाती हैं।



हेपेटाइटिस के प्रकार और लक्षण

लिवर में संक्रमण और सूजन की स्थिति को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस वायरस संक्रमण है, जिसके पांच प्रमुख प्रकार हैं- हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी,

हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई।

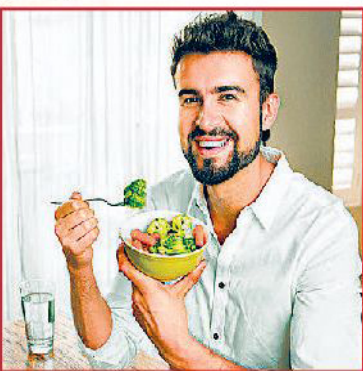
हेपेटाइटिस ए और ई: इन दोनों का वायरस दूषित खाद्य पदार्थों और प्रदूषित पेयजल के जरिए व्यक्ति को संक्रमित करता है। इसलिए दोनों हेपेटाइटिस से बचाव के लिए स्वच्छ खाद्य पदार्थ ग्रहण करें और शुद्ध जल पिएं। इन दोनों हेपेटाइटिस में लगभग 1% मरीज गंभीर स्थिति में पहुंचते हैं। इन मर्जों से ग्रस्त लोगों का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। अगर समुचित इलाज नहीं कराया गया तो हेपेटाइटिस ई गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भस्थ शिशुओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

हेपेटाइटिस बी: इससे बचाव के लिए टीका (वैक्सीन) उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ दवाओं से इस मर्ज को नियंत्रित किया जा सकता है।

हेपेटाइटिस सी: इसके इलाज में दवाएं काफी हद तक कारगर हैं।

हेपेटाइटिस डी: जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है, वही हेपेटाइटिस डी से ग्रस्त होते हैं। मरीज के लक्षणों के आधार पर इसका इलाज किया जाता है।

प्रस्तुति: विवेक शुक्ला



का संक्रमण होता है।

स्वास्थ्य के लिए लाभकारी कोकम



कंट्रोल रखता है और दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। कोकम में विटामिन-बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो

हमारी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। कोकम का सेवन न्यूरोनल विकास की क्रिया में मदद करता है, जिससे दिमागी शक्ति बढ़ती है, पॉजिटिविटी आती है। वजन घटाने में सहायक: इसके फल को पानी में उबाल कर और छानकर पीने से वजन कम करने में काफी सहायता मिलती है। दस्त होने पर कोकम के फलों का चूर्ण ठंडे दूध में मिलाकर पीने से आराम मिलता है। इसे एसिडिटी के इलाज के लिए भी जाना जाता है।

लू से बचाए: गर्मी में कोकम का शर्बत पीने से लू से बचाव होता है। प्यास बुझाने वाला यह एक ऐसा शर्बत होता है, जिसकी तासीर ठंडी होती है।

कैसे इस्तेमाल करें: कोकम को इमली की तरह सुखे फल के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। इसे इस्तेमाल करते समय इसके छिलके को काटा नहीं जाता, इसे साबूत ही सुखाया जाता है। सुखाने के दौरान इनमें थूल मिट्टी चली जाती है, इसलिए इसे संग्रहित करते समय अच्छी तरह साफ करके रखना चाहिए।

उपयोगी फल / राजकुमार 'दिनकर'

कोकम का वानस्पतिक नाम गारिनिया इंडिका है। मूल रूप से यह कोंकण इलाके का पेड़ है। इसके फल में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसका व्यापारिक इस्तेमाल भी होता है। कोकम के फल गहरे जायंती से लेकर काले रंग के होते हैं। इसका फल चिपचिपा और टेढ़े-मेढ़े किनारे वाला होता है। अकसर इसे आधा काटकर घृष में सुखाकर भारतीय रसोई में मसाले की तरह इस्तेमाल होता है। इसे आमसल कोकम या कोकम भी कहा जाता है। महाराष्ट्रियन, कोंकण और गुजराती व्यंजनों में इसका काफी इस्तेमाल होता है। खट्टे-मीठे स्वाद वाले कोकम को इमली का अच्छा विकल्प माना जाता है।

होते हैं कई गुण: कोकम खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। जो लोग अकसर बीमार रहते हैं, उन्हें इसका नियमित सेवन करना चाहिए। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीइंफ्लेमेट्री गुणों से भरपूर होता है। यह रक्त में शुगर को

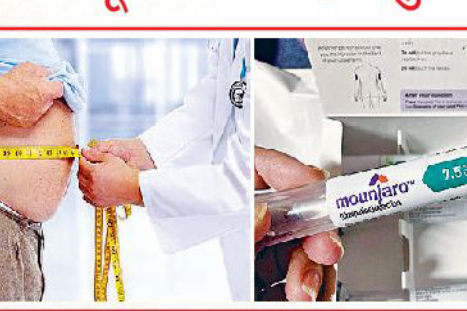
न्यू ट्रीटमेंट राजनी ओरोज़

मोटापा या ओबेसिटी आज दुनिया भर में महामारी का रूप लेता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार मोटापा, डायबिटीज, कैंसर, लिवर डिजीज, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, डिप्रेसन, स्लीप एपनिया जैसे कई गंभीर बीमारियों की वजह होने के साथ असमय होने वाली मौत के कारकों में दूसरा बड़ा कारण भी है। भारत की बात करें तो करीब 7-8 करोड़ लोग गंभीर मोटापे से ग्रस्त हैं। 'लैसैट' की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक वयस्क आबादी में 9.8 प्रतिशत महिलाएं और 5.4 प्रतिशत पुरुष मोटापे का शिकार हैं। तकरीबन 8 करोड़ लोग गंभीर मोटापे का शिकार हैं, जिनमें 1.25 करोड़ बच्चे हैं, जिनका बीएमआई इंडेक्स रेट 30 या अधिक है। जबकि 18-25 बीएमआई वाला व्यक्ति हेल्दी की श्रेणी में आता है। हालांकि ओबेसिटी को दूर करने के लिए दुनिया भर में कई तरीके अपनाए जाते हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी के अलावा रैस्मिटीरोन, स्मैलेग्लुटाइड जैसे ड्रग्स पहले से ही प्रचलन में हैं। पिछले महीने एक अमेरिकी कंपनी ने मुंजारो या ट्रायजेटाइड इंजेक्शन लॉन्च किया। इसके टायल में काफी सफलता मिली है।

कैसे दी जाती है दवा: ओबेसिटी से ग्रस्त व्यक्ति को मुंजारो का इंजेक्शन सप्ताह में एक बार दिया जाता है। व्यक्ति पेट, बांह या पैर पर यह इंजेक्शन लगाया सकता है।

हाल में एक अमेरिकन कंपनी ने मोटापा नियंत्रित करने के लिए मुंजारो दवा लॉन्च की है। यह कैसे काम करती है, कितनी कारगर है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस बारे में जानिए।

ओबेसिटी दूर करने में हेल्पफुल मुंजारो



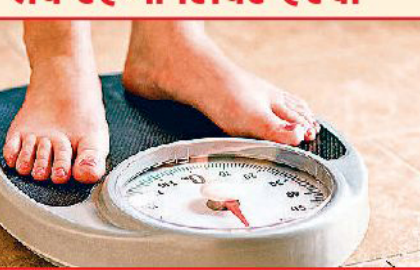
कैसे करता है अस्सर: हमारे ब्रेन के स्टेटाइटी सेंटर में दो तरह के हार्मोन निकलते हैं- जीएलपी वन (ग्लूकोगन लाइक पेप्टाइड वन) और जीआईपी (ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलिपेप्टाइड)। ये हार्मोन हमें पेट भरने का अहसास दिलाते हैं, जिससे हम खाना बंद कर देते हैं। मुंजारो दवाई इन हार्मोन के रिसेप्टर पर काम करके अलीं स्टेटाइटी की फीलिंग कराती है। यानी थोड़ा खाना खाने के बाद ही व्यक्ति को पेट भरे होने का अहसास होता है और उसका कैलोरी इन्टेक कम हो जाता है। यह खाना डाइजेस्ट करने या पेट की मूवमेंट को रफ्तार को कम कर देता है। यानी डाइजेशन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे खाना व्यक्ति के पेट में

उपरांत ही मुंजारो इंजेक्शन लेना चाहिए। टाइप-1 डायबिटीज थाइराइड कैंसर, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाजिया सिंड्रोम जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को मुंजारो इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स: हालांकि ओबेसिटी कम करने वाली दवा कारगर साबित हो रही है। लेकिन इनके शरीर पर कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि फैट के साथ शरीर का मसल्स-मास कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति कमजोर, थकान महसूस करता है। इसके अलावा मुंजारो दवाई लेने पर शुरू में व्यक्ति को पेट दर्द, गैस बनना, उल्टियां आना, घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिसके लिए हल्का सुपाच्य खाना खाने, ओवरसॉलिंग न करने की सलाह दी जाती है। धीरे-धीरे शरीर को आदत होने पर साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। पेशेंट आहार में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन रिच खाना ले सकता है।

वेट ऐसे रहेगा मॉटेन: वजन कम करने के लिए सिर्फ मुंजारो पर निर्भर रहना सही नहीं है। इसके साथ व्यक्ति को स्वस्थ जीवनशैली अपनानी भी जरूरी है। जिसमें संतुलित और पौष्टिक आहार लेने के साथ नियमित व्यायाम करना बहुत जरूरी है। ताकि दवाई बंद करने के बाद वजन दोबारा न बढ़े।

(साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एंडोक्राइन सोसाइटी, इंडिया के प्रेसिडेंट डॉ. संजय कालरा से बातचीत पर आधारित)

तब रहेगा लिवर हेल्दी



बचें। सोयाबीन, अलसी, डोल्डली, अखरोट, सौंद्रस और अंकुरित अनाजों को आहार में वरीयता देना लिवर के लिए लाभदायक है। इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करें।

आप हेल्थ कॉन्व्यास है तो योगाभ्यास रेग्युलर करते ही होंगे। लेकिन योगाभ्यास आप आराम से कर सकें और इसका सही लाभ आपको मिले, इसके लिए आपको सही योगा मैट का यूज करना चाहिए। कैसा हो आपका योगा मैट, जानिए।

योगासन के लिए कैसा हो आपका योगा मैट

सजेशन राजकुमार

आजकल योग का क्रेज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। वकिंग हो या नॉन वकिंग किसी भी आयुवर्ग के लोग योग के स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए इसे सहजता से अपना रहे हैं। अब आप योगासन सीखने की शुरुआत कर रहे हैं या सालों से इसे कर रहे हैं, तो योगा मैट का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। योगा मैट इसलिए जरूरी है, क्योंकि योगासन करने के दौरान बैठने या लेटने के लिए हमें किसी ऐसी मैट की जरूरत होती है, जिससे हमारे जोड़ों पर दबाव न पड़े, शरीर की जमीन पर पकड़ स्थिर रहे। योगा मैट के जरिए यह सब संभव है। अब सवाल है योगा मैट खरीदते समय किन बातों का ख्याल रखें?

क्वालिटी हो सही: बाजार में सस्ते या कड़े लो क्वालिटी के योगा मैट भी उपलब्ध हैं, लेकिन हमें उसकी गुणवत्ता देखकर खरीदना चाहिए, क्योंकि आम सी दिखने वाली योगा मैट पर लगातार पैरों और शरीर का दबाव पड़ने से यह खराब हो जाती है। अच्छी क्वालिटी की योगा मैट कंफर्टेबल और अच्छी पकड़ देती है। इसका स्पंज हमारे शरीर के दबाव को संतुलित करता है और इसकी मोटाई एक आरामदायक वर्कआउट सुनिश्चित करती है, क्योंकि इससे हमें सही कुराणिंग मिलती है। आजकल ये योगा मैट अलग-अलग तरह की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में उपलब्ध होते हैं। हमें अपनी बाँधी के आकार के अनुरूप ही योगा मैट का चयन करना चाहिए। इसकी मोटाई



पैरों को उतनी ही बेहतर कुराणिंग मिलेगी। योगासन के द्वारा शरीर के इन अंगों पर ज्यादा दबाव डलने के कारण इनमें चोट न लगे, इसलिए मोटी योगा मैट का चयन करना चाहिए। योगासन के लिए मैट की मोटाई 1/8 से 1/2 इंच, पाइलेट्स के लिए 1/2 इंच मोटी और नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए 1/2 इंच से 2



का भी चयन कर सकते हैं। करते रहें सफाई: योगा मैट पर योग करने के दौरान शरीर से लगातार पसीना निकलता है, जिसके कारण यह चिकने और गंदे हो जाते हैं। अगर इसे साफ न रखा जाए तो इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए योगा मैट की रेग्युलर सफाई रखें।

भारतीय यात्रियों से भरे विमान की सफल इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से बचा संकट

काठमांडू। 12 भारतीयों के साथ उड़ान भर रहे एक विमान में अचानक खराबी आ जाने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। सभी को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक हवा में उड़ान भर रहे एक विमान के 'हाइड्रोलिक' प्रणाली में खराबी आने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। इसके बाद तत्काल आपात स्थिति में विमान को काठमांडू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारने का फैसला लिया गया। पायलट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इसमें 12 भारतीय यात्री भी सवार थे। एयरलाइन के एक अधिकारी ने बताया कि माउंट एवरेस्ट क्षेत्र के प्रवेशद्वार तुक्ला से रामेछाप जा रहे निजी कंपनी 'सीता एयर' के विमान में तकनीकी



खराबी का पता चलने के बाद उसे त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया। अधिकारी ने बताया कि डोर्नियर विमान में 12 भारतीय, दो नेपाली और चालक दल के तीन सदस्य सवार थे।

सभी यात्री सुरक्षित
सही समय पर सटीक फैसला लिए जाने के चलते विमान को काठमांडू एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक उतारा गया। विमान के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसे ट्रैक्टर की

मदद से पार्किंग स्थल तक ले जाया गया। अधिकारी ने बताया इस विमान में 'हाइड्रोलिक प्रेशर' में कमी का संकेत मिला। विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं।

रणथम्भौर में बाघिन का हमला, त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत

सवाईमाधोपुर। सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर से एक बेहद दर्दनाक और चौंका देने वाली घटना सामने आई है। दोपहर करीब तीन बजे दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के बीच उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बाघ जंगल से निकलकर आया और छह साल के मासूम बच्चे को उठाकर ले गया। इस हमले में बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी लगते ही वनविभाग की टीम और अफसर जंगल की ओर दौड़े। साथ ही एहतियातन गणेश मंदिर मार्ग को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद किया। इस दौरान झाड़ियों के बीच बाघिन काफी देर तक बच्चे के पैर पर पंजा रखकर बैठी रही।

करीब दो घंटे बाद वनविभाग ने बाघिन को वहां से हटाकर बच्चे के शव को बरामद किया। मृतक बच्चे की पहचान कार्तिक सुमन (7) पुत्र द्वारका माली निवासी गोहटा थाना देई खेड़ा (बूंदी) के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शी रामसिंह ने बताया कि दोपहर 3 बजे श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। गिने-चुने लोग ही मंदिर की तरफ से दर्शन कर पैदल लौट रहे थे। अचानक बाघिन झाड़ियों



से निकलकर आई और बच्चे पर हमला कर दिया। बाघिन ने बच्चे की गर्दन को मुंह में दबाया और झाड़ियों से होकर पहाड़ियों की तरफ ओझल हो गई।

इस घटना से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया और वे भयभीत हो गए। वहीं प्रत्यक्ष घटना को देखकर दादी वहां जोर-जोर से रोने लगी और बेसुध हो गई। लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना वन विभाग को दी। जानकारी लगते ही डीएफओ और वनकर्मियों की टीम जंगल की ओर दौड़ी और एहतियातन श्रद्धालुओं को

बाहर निकालकर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को बंद करवाया। इस दौरान वनविभाग ने कैमरों की जांच करवाई तो बाघिन सुलताना झाड़ियों के बीच बच्चे के ऊपर पंजा रखकर बैठी नजर आई। वन विभाग के अधिकारी बाघिन से बच्चे को छुड़वाने के लिए मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास किए। इसके बाद वन विभाग ने पटाखों का उपयोग कर बाघिन को वहां से हटाया।

हालांकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी और उसका पेट फटा हुआ था। वनविभाग ने देर

शाम 4 बजकर 50 मिनट पर शव को बरामद किया। बाघिन के बच्चे को उठाने के बाद बच्चे के साथ आई दादी का रोते-रोते बेसुध हो गई। जानकारी के अनुसार वह अपने पोता-पोती के साथ त्रिनेत्र गणेश के दर शादी का निमंत्रण देने आई थी। उसके साथ उसकी एक पोती भी मौके पर मौजूद थी। ये दोनों बच्चे उसके बड़े बेटे के बताए जा रहे हैं। हालांकि बेसुध होने के कारण वह वनविभाग को अपना नाम पता और गांव तक का नाम नहीं बता पाई है।

पुणे में शुरू हुआ भारत-उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास 'इस्टलिक' का छठा संस्करण

पुणे। भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'इस्टलिक' का छठा संस्करण बुधवार को विदेशी प्रशिक्षण नोड, पुणे के आंध में शुरू हुआ। यह अभ्यास 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। 60 सैन्यकर्मियों की भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व जाट रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना की एक बटालियन कर रही है।



रक्षा मंत्रालय के अनुसार, संयुक्त अभ्यास 'इस्टलिक' एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह भारत और उज्बेकिस्तान में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के तरमेज जिले में हुआ था। इस वर्ष अभ्यास का विषय अर्ध-शहरी परिदृश्य में ज्वॉइंट मल्टी डोमेन उप-पारंपरिक संचालन की थीम पर आधारित है। यह एक निर्धारित क्षेत्र पर कब्जा करने वाले आतंकवादियों

को जवाब देने पर केंद्रित रहेगा। अभ्यास में ड्रोन की तैनाती, मानव रहित विमान से निपटने के उपाय और वायु सेना की ओर से अशांत क्षेत्रों में सैन्य बलों को बनाए रखने के लिए रसद सहायता पहुंचाना भी शामिल होगा।

अभ्यास के दौरान सेना और वायु सेना के विशेष बल एक हेलीपैड को सुरक्षित रखेंगे, जिसका उपयोग आगे की कार्रवाइयों के लिए आधार के रूप में किया जाएगा। संयुक्त अभ्यास 'इस्टलिक' का छठा संस्करण दोनों पक्षों को संयुक्त उप-पारंपरिक संचालन करने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने में सक्षम

RBSE ने शुरू की रिचेकिंग व्यवस्था

-गणित से होगी शुरुआत, छात्रों को मिलेगा दोहरा लाभ

जयपुर। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस साल से बोर्ड की परीक्षा में गणित सब्जेक्ट में रिटोटलिंग के साथ-साथ रिचेकिंग की व्यवस्था का प्रावधान शुरू कर दिया गया है।



रिचेकिंग व्यवस्था
रिचेकिंग व्यवस्था के तहत, छात्रों को अपने परीक्षा परिणामों की जांच कराने का अवसर मिलेगा। यदि किसी छात्र को लगता है कि उसके नंबर सही से नहीं जोड़े गए हैं या उसके आंसर शीट का टोटल सही से नहीं किया गया है, तो वह रिचेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है।

इस प्रक्रिया में, स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स की फिर से जांच की जाएगी और यदि कोई गलती पाई जाती है, तो उसे सुधारा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ने गणित विषय में रिटोटलिंग के साथ रिचेकिंग की व्यवस्था को पायलट

प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। यदि यह व्यवस्था सफल रहती है, तो आगामी वर्षों में सभी विषयों में रिटोटलिंग के साथ रिचेकिंग का प्रावधान भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का उद्देश्य छात्रों को न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। इस व्यवस्था से छात्रों को अपने परीक्षा परिणामों के प्रति अधिक आत्मविश्वास होगा और वे अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने में सक्षम होंगे।

शिक्षित राजस्थान की ओर कदम: सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शुरू हुआ डिजिटल प्रवेश उत्सव

-राज्यभर के स्कूलों में घर-घर सर्वे, ऐप आधारित डेटा कलेक्शन और दो चरणों में चलेगा अभियान

जयपुर। निजी स्कूल की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में हाल में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें डिजिटल प्रवेश उत्सव से तीन से 19 साल के बच्चों की स्कूल में शत प्रतिशत ठहराव की कोशिश की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कार्य योजना बनाई व दो चरण में इसे पूरा करने का जिम्मा शिक्षकों को दिया। डिजिटल प्रवेश उत्सव के अभियान के लिए शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 15 अप्रैल से 16 मई तक पहला चरण और एक जुलाई से 18 अगस्त तक दूसरा

चरण पूरा किया जाएगा। संबंधित स्कूल की परिक्षेत्र में उस स्कूल के शिक्षक घर-घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। सर्वे से स्कूल में नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए अस्थायी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए ड्रॉप आउट और शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल भेजने के लिए शिक्षक अभिभावकों से मिलकर काम करेंगे। दोनों चरणों में पहले स्तर पर ऐसे बच्चों को चिह्नित किया जाएगा और बाद में CRC मांड्यूल में रिकॉर्ड रखा जाएगा।

ऐप से तैयार होगा डेटा बेस : शिक्षक ऐप से अभियान के तहत काम और बच्चों का चिह्निकरण और रिकॉर्ड का डेटाबेस तैयार करेंगे। इसके लिए शिक्षकों को अपने मोबाइल में शिक्षक ऐप डाउनलोड कर अपनी लॉगिन आईडी से शुरू करना होगा। अभियान में किस तरह से काम होगा। इसे लेकर 16 और 17 अप्रैल को शिक्षकों को ऑनलाइन कार्यशाला से प्रशिक्षित किया जाएगा।

आंगनवाड़ी का लगे सहयोग: अभियान के तहत स्कूल क्षेत्र की आंगनवाड़ी के बच्चों को जोड़ने के लिए आंगनवाड़ी का सहयोग लिया जाएगा। आंगनवाड़ी में पढ़ रहे कक्षा एक में प्रवेश के लिए पात्र विद्यार्थियों का डाटा लेकर उन्हें नजदीकी स्कूल में दाखिला दिलाने के साथ अस्थाई प्रवेश प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा।

मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शांतिगेंड, जोरावर सिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार्यालय 4312 मोहल्ला नायकों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, नाहरबाड़ा, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। संपादक मुन्ना खान मॉ. 08058969180 कार्यालय फोन- 0141-2609886.